THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) No Special Task Force was constituted by the Government to examine, among other things, the question of setting up of a high quality and self-finnacing autonomous colleges and institutions which could be authorised to award their own degrees. However, a Task Force constituted to examine the amendments proposed by the UGC in the UGC Act, has recently submitted its report. The Task Force, inter alia, has suggested amendments in the UGC Act so that Central Government may make rules for institutions and/or universities, colleges, whether self-financing or otherwise so that they could also have right to confer degrees.

स्कूलों में कृषि शिक्षा

1961. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के बाद कृषि शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या जैव-कृषि (ऑरगेनिक फार्मिंग) जैसे नए विषयों को उसमें शामिल किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महिला समृद्धि योजना

1962. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने महिला समृद्धि योजना को जारी न रखने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना को सफल बनाने हेतु क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (ग) चूंकि महिला समृद्धि योजना को कार्यान्वित करने की परिचालन लागत बहुत अधिक थी, इसलिए योजना आयोग ने इस स्कीम के मूल्यांकन पर विचार करने तथा विभाग से विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस स्कीम को इन्दिरा महिला स्कीम में मिला देने की सलाह दी है। संशोधित स्कीम का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है।

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर व्यय

1963. **श्री राजमोहिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का प्राक्कलन क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के मद पर कुल 20,000 करोड़ रुपये मात्र व्यय किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) शिक्षा विभाग ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी प्रस्ताव के अन्तर्निहित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था। समिति ने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य तौर पर पांच वर्षों की अवधि के लिए 40,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान किया था।

(ग) शिक्षा विभाग के लिए नौवीं योजना (1996—2002) का परिव्यय 20,381.00 करोड़ रुपये है।